RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार, 17 नवंबर 2022 वर्ष 04 अंक 182 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

शिंदे-फडणवीस सरकार देगी 1 लाख नौकरियां

...'इस' क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर

मुंबई : विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ शिंदे-फडणवीस सरकार पर महाराष्ट्र के युवाओं की नौकरी खोने का आरोप लगा रहा है क्योंकि राज्य में परियोजनाएं दूसरे राज्यों में जा रही हैं। विरोधियों के इन आरोपों का जवाब देने के लिए कौशल विभाग की पहल पर एक लाख से अधिक रोजगार देने के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अब शिंदे-फडणवीस सरकार 1 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रही है। आज 1 लाख से ज्यादा नौकरियों के लिए एमओयू साइन किए गए हैं। समारोह राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कौशल रोजगार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मैंने तय किया कि हमारी सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सरकारी नौकरी पर लगी अघोषित रोक को हटा दिया। 10 लाख रोजगार देने का फैसला किया है। उसके तहत राज्य सरकार की ओर से 75 हजार बेरोजगारों को नौकरी देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए।

इस सेक्टर में नौकरी का मौका...

इस कार्यक्रम में 44 नामी उद्यमियों, प्लेसमेंट एजेंसियों, कौशल विभाग के कमिश्नर के साथ रोजगार के लिए एमओयू साइन किया गया। इस समझौते से राज्य के एक लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसमें 10वीं पास-फेल, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा धारक, फामेर्सी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आतिथ्य, मीडिया और मनोरंजन, निर्माण, खुदरा, बैंकिंग के क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री जैसी शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे।

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या!

सुसाइड नोट में क्या लिखा?

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के धुले जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा कि मृतक की पहचान प्रवीण विश्वनाथ कदम के रूप में हुई है. इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर मंगलवार को घटना से पहले एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था उसके सुसाइड के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए.

दीक्षांत समारोह की तैयारी में लिया था हिस्सा

अधिकारी ने आगे बताया कि 21 नवंबर को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था. इस समारोह की तैयारी में मंगलवार दोपहर को प्रवीण विश्वनाथ कदम ने हिस्सा लिया था. दरअसल, प्रवीण विश्वनाथ कदम पुणे से आने के बाद 2019 से धुले के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तैनात था. अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की शाम को जब उनके कुछ दोस्तों ने कमरे का दरवाजा बंद पाया तो दरवाजे को

खटखटाया लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

सुसाइट नोट में लिखा

इसके बाद दोस्तों ने खिड़की से झांककर देखा तो प्रवीण विश्वनाथ कदम फंदे पर लटका हुआ था. उन्होंने तुरंत थाने में इंस्पेक्टर नितिन देशमुख को सूचना दी. इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. अधिकारी ने कहा कि उन्हें कमरे में एक नोट मिला है जिसे प्रवीण विश्वनाथ कदम ने लिखा था. इसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी मौत के लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए. पुलिस ने कहा कि नासिक में रहने वाले उनके परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी गई है. वहीं अधिकारी ने कहा कि इस मामले में दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है.

महाराष्ट्र कोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज का दिया आदेश...!

समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी करने का मामला

महार जाति को लेकर किया अपमानित- समीर वानखेड़े

यह मामला तब का है जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि फजी दस्तावेजो के आधार पर समीर ने सरकारी नौकरी हासिल की. साथ ही उस दौरान का है जब नवाब मलिक का दामाद ड्रग्स मामले में जेल में था और आर्यन खान ड्रग्स केस सुर्खिंयों में था. समीर का आरोप था कि नवाब मलिक ने उनके महार जाती को लेकर उन्हें अपमानित किया था.

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के वासिम ज़िले के अडिशनल सेसंस जज ने पूर्व मंत्री व NCP नेता नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज के आदेश दिए हैं. दरअसल, नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी का आरोप है. कोर्ट का आदेश है कि नवाब मलिक पर IPC 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया जाए. समीर वानखेड़े के चचेरे भाई संजय वानखेड़े ने वासिम ज़िला अदालत में याचिका की थी और उसी याचिका पर ऑर्डर आया है. संजय वानखेड़े ने पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी जिसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई. संजय का आरोप है की उनका परिवार महार जाती (दलित) है और नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जातीय टिप्पणी कर परिवार को मानसिक प्रताड़ना दी. न्यायाधीश एच एमदेश पांडे ने वाशिम पुलिस को इस पूरे मामले का जांच करने से लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा कि साल 2021 नवंबर में शिकायत भेजे जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही कहा गया कि, लगाए गए आरोपों को देखते हुए मामले की जांच आवश्यक है.

संजय राउत की मांग...

श्रद्धा के हत्यारे को बीच चौराहे दें फांसी

मुंबई : शिवसेना नेता संजय राउत जेल से बाहर आ गए। जब से वह बाहर आए तब से उन्होंने शिंदे-फडणवीस सरकार पर हमला बोल दिया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि, बालासाहेब ठाकरे की समाधि स्थल पर सभी को जाना चाहिए, लेकिन जो वहां माथा टेकता है, उसे अच्छे मन से जाना चाहिए। बता दें कि, आज एकनाथ शिंदे गुट शिवजी पार्क में बालासाहेब के स्मारक पर जाकर उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए शिंदे गुट पर हमला किया है। उन्होंने शिंदे गुट से अपील भी की है कि वे अपने हाथों में रखे कटार अलग रखें और स्मारक पर आएं। इसबीच संजय राउत ने दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस पर प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा है कि इस मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, हत्यारे को बिना मुकदमा चलाए फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा, बालासाहेब ठाकरे इस देश और दुनिया के हैं। बस अपने हाथ में रखें खंजर साइड में रखे और फिर स्मारक पर हाथ जोड़ने आए। खंजर को एक तरफ रखें और फिर बालासाहेब को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। बालासाहेब सब देखते हैं, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। जिन लोगों ने बालासाहेब ठाकरे की पीठ में छुराघोंपा है, उनका आज तक कुछ अच्छा नहीं हो आया है, इतिहास इस बात का गवाह है। इसलिए बालासाहेब के समाधि स्थल पर सभी को जाना चाहिए, लेकिन जो उनके सामने नतमस्तक होता है, उसे अच्छे साफ मन से जाना चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारी बेटी की हत्या की गई, वह बेहद चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है।

संपादकीय / लेख

धर्मांतरण की चुनौती...!

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

जब देश की शीर्ष अदालत जबरन धर्मांतरण को चुनौतीपूर्ण मुद्दा मानकर केंद्र सरकार से कदम उठाने को कहती है तो विषय की गंभीरता का अहसास होता है। अदालत का मानना है कि देश में धार्मिक आजादी है लेकिन इसका मतलब जबरन धर्मांतरण की आजादी होना कदापि नहीं है। इस तरह की कोशिशें जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चुनौती हैं, वहीं नागरिकों की धर्म और अंत:करण की स्वतंत्रता को भी बाधित करती हैं। अदालत ने इस बाबत केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाने को कहा है और बाईस नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है ताकि मामले में माह के अंतिम सप्ताह में सुनवाई हो सके। लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि देशी-विदेशी एजेंसियां धर्मांतरण के जरिये देश का सांस्कृतिक चरित्र बदलने की कोशिशों में लगी हैं। खासकर आदिवासी व पिछड़े इलाकों में छलबल व धनबल के जरिये ऐसी कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल, यह संकट हमारे समाज में सामाजिक व आर्थिक असमानता से उपजा प्रश्न भी है। जिन आदिवासियों व निचले जातिक्रम में आने वाले समूहों को समानता का हक नहीं मिला, उन्हीं तबकों में व्याप्त आक्रोश को धर्मपरिवर्तन का अस्त्र बनाया जाता है। जातीय दंभ से त्रस्त समाजों में यह आक्रोश नजर भी आता है। अशिक्षा भी इसके मूल में एक बड़ा कारण है। निस्संदेह, सामूहिक धर्मांतरण की कोशिशें कालांतर सामाजिक तानाबाना भी बदलती हैं। ये कोशिशें बाद में सामाजिक टकराव की वाहक बनती हैं। वहीं राजनीतिक हित साधने का साधन भी होती हैं। जो बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी चुनौती पैदा कर सकती हैं। ऐसी चिंता अदालत ने भी जतायी है। अदालत ने लोभ-लालच से कराये जाने वाले मतांतरण को गंभीर मामला बताते हुए इसे रोकने की दिशा में तुरंत कदम उठाने को कहा है। हालांकि, देश में कुछ राज्यों ने धर्मांतरण रोकने के लिये कानून भी बनाये हैं, लेकिन ये धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर अंकुश लगाने में कारगर साबित नहीं हुए हैं। यही वजह कि राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण रोधी प्रभावी कानून बनाये जाने की मांग की जाती रही है।

हाल के दिनों में देश के आदिवासी इलाकों से इतर पंजाब में भी धर्मांतरण के मामलों में तेजी आने की बात कही जाती रही है। धन का प्रलोभन देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में धर्म विशेष की गतिविधियों में अप्रत्याशित तेजी आई है। कुछ समय में बड़ी संख्या में उपासना स्थल बनाये गये हैं। जिसके चलते पिछले पांच वर्षों में राज्य के कई जनपदों में सामाजिक संरचना में बदलाव देखने की बात कही जा रही है। यह बदलाव पिछड़े व वंचित वर्गों में ज्यादा देखा जा रहा है। निस्संदेह, देश में धार्मिक आजादी है और हर व्यक्ति को अपने अंत:करण की स्वतंत्रता है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे धर्म के लोगों के धर्म परिवर्तन के लिये किया जाना अनुचित ही है। आरोप है कि अंधविश्वास, अज्ञानता, डर, लालच को अस्त्र बनाकर यह धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कुछ इलाकों में महज अनाज देकर ही धर्म परिवर्तन करने की बात कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कही है। कुछ लोगों को जीवन की रोजमर्रा की मुश्किलों का समाधान धर्म परिवर्तन में बताया जा रहा है। निस्संदेह, किसी की विवशता का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन कराना अनैतिक कृत्य ही कहा जायेगा। पिछले दिनों देश में पश्चिम बंगाल, नेपाल व राजस्थान से लगे सीमांत इलाकों में धार्मिक आधार पर जनसंख्या के स्वरूप में बदलाव को लेकर राष्ट्रीय एजेंसियां चिंता जता चुकी हैं। वे इस सुनियोजित कोशिश को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बताती रही हैं।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

संजय राउत का दावा अगला सीएम एमवीए का होगा

2024 तक जारी रहेगी हमारी लड़ाई, अपने जन्मदिन पर बोले संजय राउत

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी का होगा। संजय राउत बीते मंगलवार को अपना जन्मदिन मना रहे थे। राउत ने कहा कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और यह 2024 तक चलेगी। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त तक जेल में रहूंगा या कि बाहर। लेकिन यह तो तय है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए से होगा। वहीं इस वक्त शिवसेना लगातार यह कहती नजर आ रही है कि जल्द ही महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं।

उद्धव गुट का दावा, 6 महीने के भीतर होंगे चुनाव

बीजेपी और शिंदे गुट के महाराष्ट्र में मिलकर सरकार बनाने के बाद से ही लगातार उद्धव गुट वाली शिवसेना जल्द ही चुनाव होने का दावा करती रही है। इसको लेकर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद विनायक राउत ने भी कहा कि अगले छह महीनों में राज्य में मध्यावधि चुनाव जरूर होंगे। उन्होंने कहा कि 'विधायकों की अयोग्यता और सरकार की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसको लेकर जनवरी से फरवरी तक फैसला सुनाया जाना है। विनायक राउत ने कहा कि यह तो स्पष्ट है कि परिणाम क्या होगा। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद मध्यावधि विधानसभा चुनाव कराने होंगे।

शिवसैनिक अभी भी हमारे साथ: राउत

संजय राउत ने कहा कि शिव सैनिक अभी भी शिवसेना के साथ हैं। राउत ने कहा कि 'मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जेल के बाहर अपना जन्मदिन मना रहा हूं। राज्य की राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर और मैली हो चुकी है। महाराष्ट्र में अविश्वास और राजनीतिक प्रतिशोध है। यह महाराष्ट्र की परंपरा नहीं थी। राउत ने कहा कि ठाणे में जितेंद्र अवध के खिलाफ एक फर्जी मामला है, इसे रोकना होगा। शिवसैनिकों का खून इतना सस्ता नहीं है, उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। संजय राउत ने कहा 'मुझे यकीन है कि साल 2024 तक राज्य में एमवीए का ही सीएम होगा।'

एसटी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!

34 प्रतिशत महंगाई भत्ता लागू

मुंबई : राज्य के एसटी कर्मचारी पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, इसी बीच राज्य सरकार ने आज एसटी कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। शिंदे-भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया है और राज्य सरकार ने एसटी निगम को पत्र भेजा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह एसटी कर्मचारियों को भी 34 फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला कुछ समय के लिए लटका हुआ था। चूंकि इस प्रस्तावित भत्ते पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए एसटी ट्रेड यूनियन आक्रामक हो गए और उनके द्वारा विरोध भी किया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि एसटी कर्मचारियों को 28 फीसदी भत्ते से संतोष करना पड़ता है। इस बीच राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के एसटी कर्मचारियों को अब बड़ी राहत मिलेगी।

महाराष्ट्र और बिहार में सड़कों की स्थिति में कोई अंतर नहीं: रमेश

महाराष्ट्र : कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सड़क निर्माण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र और बिहार में सड़कों की हालत समान रूप से खराब है।कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे पार्टी नेता रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विपरीत महाराष्ट्र में सड़कों की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पैदल मार्च के दौरान सड़कों पर चलने में उन्हें कठिनाई हुई।

महाराष्ट्र में 10वें दिन की यात्रा विदर्भ क्षेत्र के वाशिम जिले में बुधवार को शुरू हुई। रमेश ने सवाल किया, ''मोदी सरकार में एक मंत्री हैं जिसके पास एक महत्वपूर्ण विभाग है और ऐसा माना जाता है कि शेर शाह सूरी के बाद, उन्होंने सभी सड़कों का निर्माण किया है। उनकी छवि एक 'मास्टर' सड़क निमार्ता की है। वह अपने काम की शेखी भी बघारते हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में क्या हुआ है?'' उन्होंने कहा, ''निवेश के मामले में महाराष्ट्र नंबर एक है, लेकिन मेरा कहना है कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच सड़कों के मामले में कोई अंतर नहीं है।''

रमेश ने यह भी कहा कि वह मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में 100 किलोमीटर से अधिक चले और सड़कों की खराब स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने कहा, ''हमें सड़कों पर चलने में बहुत परेशानी हुई। जब यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी तो हमें ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं हुआ।'' उन्होंने कहा कि वह सुबह में (वाशिम में) 15 किलोमीटर चले और सात किलोमीटर का रास्ता बहुत खराब था।

इतिहास को क्यों तोड़-मरोड़ रहे हो...? - अजीत पवार

मुंबई : मैंने हर-हर महादेव फिल्म की कुछ क्लिप देखी हैं, पूरी फिल्म नहीं देखी है। लेकिन बचपन से सुनता आया हूं... बाघ की नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान की अंतड़ी निकालकर मार डाला। इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान को उठाकर जांघ पर रखकर भगवान नरसिंह की तरह अंतड़ी निकालते हुए दिखाया गया है। अरे यह क्या दिखा रहे होङ्घ? इतिहास को क्यों तोड़-मरोड़ रहे होङ्घ? सरकार सेंसर बोर्ड की नियुक्ति करती है, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, इतिहास को तोड़-मरोड़ करके मत दिखाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं, ऐसे शब्दों में प्रतिपक्ष के नेता अजीत पवार ने फिल्म निमार्ताओं को फटकार लगाई। अजीत पवार ने आगे कहा कि उक्त संदर्भ में फिल्म विशेषज्ञों से मुलाकात करके जानकारी लेंगे। इसके बाद इस संदर्भ में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को जानकारी दूंगा। महाराष्ट्र से बाहर जा रहे उद्योग के बारे में अजीत पवार ने कहा कि इसके लिए सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं और उद्योगपतियों को दोबारा राज्य में लाने का प्रयास करना चाहिए।

चलते ऑटो में ड्राइवर कर रहा था छेड़छाड़, लड़की ने लगाई छलांग- वीडियो

नई दिल्ली : दुनिया में हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे मुद्दे है जो वैसे के वैसे ही बने हुए है। आये दिन महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की खबरें सामने आती है, जिस पर बिलकुल भी रोक नहीं लग रही है। जहां उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की को चौथी मंजिल से फेंका गया जिससे उसकी मौत हो गई, वही बिहार में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ क्रूरता दिखाई गई, यही नहीं बल्कि अब कुछ ऐसी ही खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सामने आई है।

जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर सामने आया है। आइए जानते है इस दिल दहला देने वाले वीडियो के बारे में जिस तरह की खबरें इन दिनों सामने आ रही है उसमें हम देख सकते है लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जी हां हाल ही में आई एक घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई है। आपको बता दें कि दरअसल यहां एक ऑटोवाला ऑटो में बैठी लड़की से साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था। ऐसे में लड़की ने लड़की ने खुदको बचाने के लिए के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी। हुआ यह कि यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आरोपी ऑटो चालक सैयद अकबर हमीद को हिरासत में ले लिया गया है। लड़की के सिर में चोट लगी है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना का वीडियो देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

अंधेरी जोगेश्वरी में नहीं भरेगा पानी

बारिश का पानी निकासी करने वाली पाइप की बढ़ेगी क्षमता

मुंबई : अंधेरी सबवे के साथ साथ दाऊद बाग,आजाद नगर , वी आर देशाई रोड आदि इलाको में बारिश के दौरान हर साल होने वाली जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता था। मनपा प्रशासन ने इस समस्या को दूर करने के लिए मोगरा नाले से जुड़ने वाली बारिश का पानी निकासी करने वाली पाइप लाइन की क्षमता बढ़ाने का निर्णय मनपा प्रशासन ने लिया है। मनपा प्रशासन ने तीन भाग में बंटवारा कर बारिश की पाइप लाइन का क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है।मनपा तीनो जगहों पर काम करने के लिए 105 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दे कि अंधेरी परिसर में पानी भरने की हर समय समस्या बनी रहती है । अंधेरी सबवे से मोगरा नाला में बहने वाला बारिश का पानी मिल्लत नगर, लोखंड वाला कमलेक्स के पास मलाड खड़ी में बह कर जाता है।मोगरा नाला की चौड़ाई कई जगहों पर काफी कम है।जिसके चलते बारिश के समय नाले का पानी बारिश के समय ऊफान कर सड़क पर आ जाता है। जिसके चलते अंधेरी के पश्चिम इलाके में कई जगहों पर पानी भरने की समस्या खड़ी होती है।बारिश में होने वाले जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए मनपा ने इस इलाके को तीन भाग में बांट कर बारिश की पाइप लाइन को चौड़ा करने का निर्णय लिया है जिससे हर साल बारिश के समय होने वाली जल जमाव की समस्या दूर होगी।वीरा देशाई रोड क्लव्हार्ट से कोर्ट यार्ड जंक्शन मार्ग से दत्ता जी सालवी रास्ता से आर टी ओ जंक्शन से लिंक रोड मार्ग और सिटी मॉल तक मोगरा नाला तक बारिश की पाइप लाइन को चौड़ा किया जाएगा।इस नाले को ऊपर से बंद किया जाएगा जिससे कचरा नाले में न जा सके।इसी तरह भरडा वाडी रोड क्लव्हार्ट से जी पी रोड होते हुए डी एन नगर मेट्रो स्टेशन के पास क्रिस्टल माल के पास मोगरा नाला क्लव्हर्त तक पाइप लाइन बिछाई जाएगी । बता दे कि मोगरा नाला को 2017 में पेटी दार बनाया गया था जिस पर 32 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। मोगरा नाला पर पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए 2021 में मनपा स्थाई समिति में मंजूरी दी गई थी लेकिन जमीन विवाद और मामला कोर्ट में प्रलंबित होने के कारण पंपिंग स्टेशन बनाने की अभी तक शुरूआत नही हो पाई है। इस पंपिंग स्टेशन को बनाने के लिए 2005 में आई प्रलय कारी बाढ़ के बाद मुंबई में 8 जगहों पर पंपिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया था। अंधेरी सबवे, दाऊद बाग, ढाकू शेठ पाड़ा, भरडा वाडी, आजाद नगर, वीरा देसाई रोड इन तीन इलाको में बरसात के समय पानी भरने की समस्या से मिलेगा छुटकारा ।

नवादा में बरसे पप्पू यादव, कहा- यहां पैसों की ताकत पर बनते MP-MLA, गरीबों को कई नहीं देखता...

नवादाः जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बुधवार को नवादा पहुंचे. वहां जहर खाकर मरने वाले छह लोगों के परिवार के परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया. इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर भी जमकर हमला बोला. कहा कि बिहार में लगातार कर्ज में डूबे परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे. ये खुदकुशी नहीं हत्या है. उन्होंने कहा कि निर्भया हत्या से पूरा देश हिल गया था. देश की सरकार बदल गई थी, लेकिन बिहार में लगातार हत्याएं हो रही इसपर कोई ध्यान नहीं दे रहा. नवादा में पैसों की ताकत पर एमपी और एमएलए बन जाते. मुख्यमंत्री फंड में बड़े-बड़े माफिया करोड़ों रुपये देते, लेकिन गरीबों को कोई नहीं देखता है.

नवादा में पैसे के बदौलत एमपी एमएलए के मिलते पद

उन्होंने कहा कि निर्भया हत्याकांड में पूरे देश हिल गया था और देश की सरकार बदल गई थी, लेकिन बिहार में लगातार हत्याएं हो रही जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा. भागलपुर बम ब्लास्ट में देश के पीएम ने भी ट्वीट किया था और बिहार के सीएम ने भी ट्वीट किया था, लेकिन छह लोगों की एक साथ हत्या पर किसी का ट्वीट सामने नहीं आया. पप्पू यादव ने कहा कि गिट्टी और पहाड़ माफिया को पनाह बिहार के सरकार दे रही है. नवादा में पैसे के बदौलत एमपी एमएलए की पद लोगों को मिलती है. वहीं मोकामा चुनाव पर कहा कि ये चुनाव बाहुबलियों का चुनाव था जहां जाति पर बाहुबली की सत्ता जमाई है. सहारा बैंक के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर सहारा पैसा नहीं चुकाएगी तो लाखों लाख लोग इसी तरह आत्महत्या करेंगे.

मामले की जांच की मांग

नवादा एवं नालंदा में सूदखोरों का ढेर है और सूदखोरों के भी हौसले बुलंद हैं. सरकार सूदखोरों पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा पा रही है. नवादा में एक ही परिवार के छह लोगों की आत्महत्या के मामले में पप्पू यादव ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं है. इन लोगों की हत्या हुई है. इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है. सरकार से यह मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच कर कॉल डिटेल निकाला. कॉल डिटेल में पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा.

कर्ज को लेकर बिहार में लगातार हो रही खुदकुशी

एक परिवार के छह लोगों के जहर खाकर मरने की घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया है. पप्पू यादव ने कहा कि कर्ज के कारण गुप्ता परिवार ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उन लोगों की हत्या की गई है. सूदखोरों के हौसले इतने बुलंद है कि पैसा नहीं देने पर बेटियों को भी उठाने की बात करते हैं. ऐसा ही मामला सहरसा में भी सामने आया जहां परिवार ने आत्महत्या कर ली. वहीं समस्तीपुर में भी पांच लोगों ने आत्महत्या की थी. मंगलवार को भी सीवान में दो बेटी ने आत्महत्या की. सभी लोग कर्ज में दबे थे.

७ महीने में १७३.४६ अरब डॉलर का हुआ देश को व्यापार घाटा

मुंबई : केंद्र की मोदी सरकार देश में विकास का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि सच्चाई ये है कि देश की अर्थव्यवस्था का जनाजा निकल रहा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, रुपए का मूल्य गिर रहा है और विदेशी मुद्रा का भंडार घटने से तिजोरी खाली खाली हो रही है। इसका प्रमुख कारण है कि देश से निर्यात घट रहा है और आयात बढ़ रहा है। इस कारण सिर्फ पिछले ७ महीने में हिंदुस्थान को १७३.४६ अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो चुका है।

मिली जानकारी के अनुसार गत अक्टूबर में देश का निर्यात १७ फीसदी घटकर २९.७८ अरब डॉलर रह गया है। अक्टूबर २०२१ में ५३.६४ अरब डॉलर के मुकाबले अक्टूबर २०२२ में आयात ५६.६९ अरब डॉलर हो गया। यानी विदेश से सामान की खरीददारी ज्यादा की गई है। दूसरी तरफ देश का माल निर्यात पिछले महीने के ३५.४५ अरब डॉलर से गिरकर २९.७८ अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात इसी अवधि में ६१.१६ अरब डॉलर से घटकर ५६.६९ अरब डॉलर रह गया। आंकड़ों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक निर्यात में गिरावट के कारण अक्टूबर में देश का कुल आउटबाउंड शिपमेंट ६.६५ फीसदी की गिरावट के साथ २९.७८ अरब डॉलर हो गया। व्यापार घाटा पिछले महीने के २५.७१ अरब डॉलर से बढ़कर २६.९१ अरब डॉलर हो गया। ये आंकड़े खुद केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को जारी किए। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान निर्यात १२.५५ फीसदी बढ़कर २६३.३५ अरब डॉलर हो गया। आंकड़ों के मुताबिक इसी अवधि में आयात ३३.१२ फीसदी बढ़कर ४३६.८१ अरब डॉलर हो गया।

बेटी ने मां पर धोखे से एलएलबी की परीक्षा पास करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया

नई मुंबई : नई मुंबई के नेरुल पुलिस स्टेशन में एक बेटी ने अपनी ही मां पर धोखे से एलएलबी की परीक्षा पास करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। नई मुंबई परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने बताया कि आरोपी महिला ने साल २००५-२००६ में मुंबई के एक कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था लेकिन वो लगभग १४ वर्षों बाद भी परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। इसके बाद लॉकडाउन में महिला ने मुंबई के एक पुलिसकर्मी की मदद से ऑनलाइन परीक्षा दी थी, जिसमें वो पास भी हो गई। लड़की का आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा के समय महिला ने कैमरा बंद कर दिया था और पूरी परीक्षा उसके पुरुष साथी ने दिया था। लड़की का कहना है कि उसे तभी से यह बात खटक रही थी। इतने दिनों बाद जब उससे रहा नहीं गया तो उसने नेरुल पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज करवाया।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार, 17 नवंबर 2022

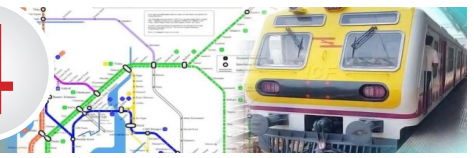

पूर्व बीजेपी पार्षद अस्मिता चौधरी के पति का अवैध निर्माण पड़ा भारी...

भिवंडी : मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण में पति की संलिप्तता उजागर होने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राजेश चौधरी की पत्नी पूर्व बीजेपी पार्षद अस्मिता चौधरी का नामांकन के साथ ही नगरसेवक पद रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा नगरसेवक पद रद्द किए जाने से तमाम पूर्व जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है।

जानें क्या है पूरा मामला

गौरतलब हो कि 2017 में भिवंडी निजामपूर शहर, महानगरपालिका चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर प्रभाग क्रं. 23 (ब) से बीजेपी की तरफ से महिला आरक्षित स्थान के लिए अस्मिता राजेश चौधरी और शिवसेना की प्रत्याशी नेहा केतन पाटील ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र जांच के दौरान तत्कालीन चुनाव निर्णय अधिकारी नंदकुमार कोष्टी के समक्ष शिवसेना प्रत्याशी नेहा केतन पाटिल ने बीजेपी प्रत्याशी अस्मिता चौधरी के पति राजेश चौधरी पर वन भूमि कब्जा कर अवैध निर्माण किए जाने का मामला संज्ञान में लाते हुए नामांकन पत्र रद्द की मांग करते हुए आवश्यक कागजात दिए थे। बीजेपी प्रत्याशी अस्मिता चौधरी के पति राजेश हरीशचंद्र चौधरी को वन विभाग द्वारा जारी अवैध निर्माण की नोटिस दिए जाने के बाद भी चुनाव निर्णय अधिकारी ने कोई सुनवाई न करते हुए अस्मिता राजेश चौधरी का नामांकन वैध करार दिया था। बीजेपी प्रत्याशी के पति के खिलाफ अवैध निर्माण शिकायत के बाद भी चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा ठोस जरूरी निर्णय नही लेने से महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अस्मिता राजेश चौधरी चुनाव जीत गई। अवैध निर्माण की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर चुनाव अधिकारी के निर्णय के खिलाफ नेहा केतन पाटील के अधिवक्ता आर. आर त्रिपाठी ने दिवाणी न्यायालय भिवंडी में याचिका दाखल कर न्याय की फरियाद की थी।

मुंबई हाईकोर्ट ने रद्द की पार्षद पत्नी की सदस्यता

अवैध निर्माण में लिप्त लोगों में हड़कंप

हाईकोर्ट के निर्णय से आगामी महानगरपालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक तमाम दावेदारों के समक्ष अवैध निर्माण में संलिप्त होने पर कड़ी कार्यवाही के आसार प्रबल हो गए हैं। हाईकोर्ट के निर्णय से अवैध निर्माण में लिप्त और चुनावी समर में उतरने वाले तमाम संभावित प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है।

नेहा पाटिल ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया...

अधिवक्ता आर. आर त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव निवडणूक निर्णय अधिकारी का गलत निर्णय रद्द कर अस्मिता राजेश चौधरी का नामांकन रद्द अमान्य कर जीत को चुनौती दी। भिवंडी कोर्ट में न्याय नहीं मिलने पर शिवसेना प्रत्याशी नेहा पाटिल ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट न्यायाधीश ने अधिवक्ता आर. आर त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पेश कागजात और तथ्यों के आधार पर करते हुए अस्मिता राजेश चौधरी का नामांकन ही अवैध करार देते हुए नगरसेवक पद रद्द कर दिया है।

महानगरपालिका चुनाव लडने के लिए पूर्णतया अपात्र अस्मिता चौधरी

हाईकोर्ट के निर्णय से अवैध निर्माण में लिप्त तमाम पूर्व और आगामी महानगरपालिका चुनाव लडने के इच्छुकों में हड़कंप मचा हुआ है। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए अवैध निर्माण में पति की संलिप्तता साबित होने पर पार्षद पद रद्द होना भिवंडी महानगरपालिका के इतिहास में ऐतिहासिक करार दिया है। कानूनी जानकारों की माने तो अवैध निर्माण में संलिप्तता उजागर होने के बाद अस्मिता राजेश चौधरी अब कभी भी महानगरपालिका चुनाव लडने के लिए पूर्णतया अपात्र हो गई हैं। हाईकोर्ट ने महानगरपालिका प्रशासन को नेहा पाटिल को पूर्व नगरसेविका के नाम से रिकार्ड में शामिल करने का आदेश भी दिया है।

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशिष शेलार के सुरक्षाकर्मियों के साथ महिला की बदसलूकी...

बीच सड़क इस कारण हुई गाली गलौज

मुंबई : मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशिष शेलार के कॉन्वॉय में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ बदसलूकी और सरकारी काम में रुकावट पैदा करने का मामला सामने आया है. इस मामले में एक महिला के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है. आशिष शेलार मंगलवार को विलेपार्ले में एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे थे कि उसी दौरान बांद्रा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास ये घटना हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेलार का कॉन्वॉय सिग्नल पर पहुंचा जो लाल हो गया था पर सुरक्षा को देखते हुए लाल सिग्नल का पालन नहीं हुआ. उसी समय कॉन्वॉय की गाड़ियों में से एक गाड़ी ने बाइक को ठोकर मार दी. इस गाड़ी को एक महिला चला रही थी जिसके बाद गुस्साई महिला पूनम पाटिल ने कॉन्वॉय के सुरक्षा रक्षकों को गाली देना शुरू किया और उनकी गाड़ी रोक ली. इस मामले में महिला के खिलाफ बांद्रा पुलिस ने क्ढउ की धारा 353,332, 504,427 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दुर्घटना में जख्मी हुए शख्स को 49.3 लाख रुपये देने का ट्रिब्यूनल का आदेश

ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 29 वर्षीय एक व्यक्ति को साल 2017 में हुई एक सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के लिए 49.33 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 01 नवंबर को पारित हुए इस आदेश में एमएसीटी सदस्य एमएम वलीमोहम्मद ने निर्देश दिया है कि जिस ऑटो की चपेट में आकर शख्स की दुर्घटना हुई थी उसके मालिक और बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से याचिका दायर करने की तारीख से लेकर दो महीने के भीतर सालाना सात फीसदी ब्याज दर के साथ राशि का भुगतान करना होगा। मंगलवार को उपलब्ध कराई गई आदेश की एक प्रति

में कहा गया है और अगर ये ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो इन्हें राशि का पूर्ण भुगतान होने तक आठ फीसदी ब्याज देना होगा। इस दिन सुनवाई के दौरान ऑटो का मालिक पेश नहीं हुआ, ऐसे में उसके खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाया गया और दूसरी तरफ बीमा कंपनी ने अलग-अलग आधार पर इसका विरोध किया। पीड़ित की ओर से पेश अधिवक्ता ने एमएसीटी को बताया कि उनका मुवक्किल नौकरी पेशा है और उन्हें महीने के 34,277 रुपये तनख्वाह के रूप में मिलती है। 11 जनवरी, 2017 को वह अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से एक टेम्पो आया और अपनी लापरवाही के चलते यहां कैडबरी जंक्शन के पास बाइक से जा टकराया। इस दौरान याचिकाकर्ता अपनी बाइक से नीचे गिर गया और उन्हें कई चोटें आईं। इतना ही नहीं, उन्हें इलाज का खर्च भी उठाना पड़ा और ट्रीटमेंट काफी लंबा चला। याचिकाकर्ता ने कहा, 'इस दुर्घटना की वजह से वह शारीरिक रूप से अक्षम हो गए और उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसी के साथ ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के दिए दस्तावेजों को स्वीकार किया और मुआवजे का आदेश दिया।'

आयकर विभाग ने मुंबई में मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के परिसरों की तलाशी ली

मुंबई : आयकर विभाग ने कर चोरी के कथित मामले की जांच के तहत बुधवार को मुंबई स्थित मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर के परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में चिकित्सा जांच एवं निदान केंद्र चलाती है। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने कंपनी के मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली।

मामले में कंपनी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर चिकित्सा जांच एवं निदान के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। उसने पिछले सप्ताह 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में कर को छोड़कर 40.5 करोड़ रुपये का समेकित लाभ होने की जानकारी दी थी।

ठाणे में शिक्षण संस्थान से जबरन वसूली, दो लोग गिरफ्तार...

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक शिक्षण संस्थान के प्रबंधन से कथित जबरन वसूली करने पर दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह जानकारी बुधवार को एक अधिकारी ने दी। भिवंडी क्षेत्र में स्थित

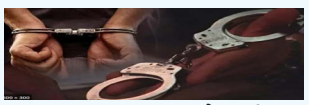

शिक्षण संस्थान परिसर में टंकी का निर्माण कराया जा रहा था। जबरन वसूली विरोधी सेल (एईसी) के वरिष्ठ इंस्पेक्टर मालोजी शिंदे ने कहा, निर्माण की अनुमति के लिए प्रबंधन से दो आरोपियों ने कथित तौर पर दो लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने कहा, बाद में, वे एक लाख रुपये ह्लसुरक्षा राशिह्व के लिए सहमत हुए। अधिकारी ने कहा, शिक्षण संस्थान के प्रबंधन के प्रतिनिधि द्वारा ठाणे शहर की पुलिस से दर्ज कराई गई शिकायत के मद्देनजर एईसी ने सोमवार को दोनों आरोपियों को फंसाया और शिकायतकर्ता से पैसे लेते हुए पकड़ लिया। 7

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com